

# घाटती घटना

सत्य के साथ... जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर, वर्ष 22, अंक - 70 - शुक्रवार 09- जनवरी 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050, एक पंजीवन. क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

## टीएमसी आईटी सेल इंजार्ज के घर-ऑफिस पर पड़े थे छापे... एक्शन के बीच फाइल उठाकर निकलीं

### ममता बोलीं... प्रधानमंत्री जी अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए

कोलकाता, 08 जनवरी 2026। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के दौरान एकावट पैदा की। वे कोलकाता में पॉलिटेक्निक कंसल्टेंट फर्म I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में जबन घुसीं और अपने साथ कई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गईं। ईडी के मुताबिक, इसके बाद मुख्यमंत्री साँल्ट लेक स्थित I-PAC कार्यालय भी पहुंचीं। यहां भी राज्य की पुलिस की मदद से अहम सबूत जबन अपने साथ ले गईं। प्रतीक जैन ममता की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। ममता ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा- मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। इस कार्रवाई के विरोध में ममता कल 2 बजे मार्च निकालेंगी।



ममता का आरोप- यह कार्रवाई घटिया और शरारती गृह मंत्री करवा रहे...

सोपम ममता ने छापेमारी को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और इसके पीछे बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्या ईडी और अमित शाह का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जप्त करना है? यह एक घटिया और शरारती गृह मंत्री है, जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। मेरी पार्टी के सभी दस्तावेज उठाकर ले गए हैं। एक तरफ वे पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। मुझे माफ करें प्रधानमंत्री जी, कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। अगर आप हमसे लड़ नहीं सकते, तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप हमारी एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे कामजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। यह सब करके, आपको जितनी सीटें मिल रही थी, वे घटकर जा रही हैं।

### मामला हाईकोर्ट पहुंचा, आज सुनवाई

सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उधर, I-PAC ने भी सच की वैधता को चुनौती दी है। मामले की सुनवाई आज जस्टिस सुरवा घोष की बेंच में होगी। वहीं, प्रतीक जैन के परिवार ने शेक्सपीयर सननी पुलिस स्टेशन में ईडी अधिकारियों के खिलाफ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत कराने का फैसला किया है।

कोलकाता पुलिस कमिश्नर, प्रतीक के आवास पर पहुंचे। कुछ समय बाद सोपम ममता बनर्जी खुद लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके घर पहुंच गईं। ममता वहां कुछ देर रुकीं जब बाहर निकलीं, तो उनके हाथ में एक हरी फाइल दिखाई दी। इसके बाद वे I-PAC के ऑफिस भी गईं। उन्होंने कहा... गृहमंत्री मेरी पार्टी के दस्तावेज उठा रहे हैं। ईडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई।

## कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं... इसलिए काटते हैं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 08 जनवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट में आवाज कुत्तों से जुड़े मामले पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बड़े घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर को लेकर चर्चा की। जस्टिस नाथ ने कहा कि कुत्ते इंसानों का डर पहचान लेते हैं इसलिए काटते हैं। इस पर एक वकील (कुत्तों के फेवर वाले) ने इनकार किया। फिर जस्टिस ने जवाब दिया कि, अपना सिर मत हिलाइए, वे बात में पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है। उधर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राज्यों ने जो आंकड़े दिए हैं, उनमें से किसी ने यह नहीं बताया कि नगर पालिकाओं की तरफ से कितने शेल्टर बनाए जाते हैं। देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर हैं। इनमें से हर एक में 100 कुत्ते रह सकते हैं। हमे इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एनिलम वेलफेयर की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट सीयू सिंह ने कुत्तों को हटाने या शेल्टर होम भेजने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कुत्ते हटाने से चूहों की आबादी बढ़ेगी। इस पर कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में कहा... तो क्या बिल्लियां ले आएं? इस मामले पर पिछले 7 महीनों में छह बार सुनवाई हो चुकी है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवाज कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तब शेल्टर में ट्रांसफर किया जाए। याचिकाकर्ता के एक वकील ने कहा हर पालतू कुत्ते का मालिक होता है। जबकि आवाज

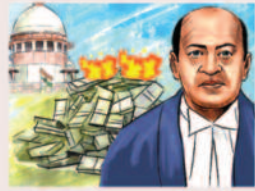


कुत्ते का कोई मालिक नहीं होता। न ही यह राज्य की जिम्मेदारी है। हालांकि राज्य का काम वैक्सिनेशन वगैरह देना है। एबीसी नियम ऐसे होने चाहिए कि मेरे घर तक का रास्ता सुरक्षित रहे। वकील (कुत्तों को हटाने के पक्ष में) ने कहा कि अदालत का आदेश सिर्फ संस्थानों तक सीमित नहीं होना चाहिए। बल्कि उसे रिहायशी इलाकों पर भी लागू किया जाना चाहिए। कुत्ते को समझाना (काउंसिलिंग) संभव नहीं है, लेकिन कुत्ते की देखभाल करने वाले या मालिक को समझाया जा सकता है। हर डॉग लवर और एनजीओ को याचिका लगाने में एक तब राशि जमा करनी होती है। इस शर्त को हटायें जाए। इस पर कोर्ट ने हल्के अंदाज में जवाब दिया... अगर हमने यह शर्त नहीं रखी होती, तो यहां पंखाल लगाना पड़ता। कुत्तों की मॉनिटरिंग के लिए पहले उनकी गिनती जरूरी है जो आखिरी बार 2009 में हुई थी।

## जज केस कांड... सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

### जवाब देने के लिए समय बढ़ाने से इनकार जस्टिस वर्मा ने महाभियोग को चुनौती दी थी

नई दिल्ली, 08 जनवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस दीपाकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दो दिन की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया। हालांकि बेंच ने जस्टिस वर्मा को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जवाब दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने से मना कर दिया। उन्हें 12 जनवरी को संसदीय समिति के सामने जवाब देना है। दरअसल, जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ लागू गए महाभियोग प्रस्ताव को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि उनसे सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे मंजूर नहीं किया। इसके बावजूद लोकसभा ने अकेले जांच समिति बना दी, जो उनके अनुसार गलत है। एक दिन पहले, 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जांच समिति के गठन में कुछ खामियां दिखाई देती हैं। हालांकि कोर्ट यह देखेगा कि क्या यह खामी इतनी गंभीर है कि पूरी कार्यवाही रद्द किया जाए। 14 मार्च को दिल्ली में जज के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में आग लगने के बाद जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। इसके बाद के घटनाक्रम में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया।



## प्रख्यात वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीविद डॉ. माधव गाडगिल का पुणे में निधन

मुंबई, 08 जनवरी 2026। महाराष्ट्र के पुणे निवासी प्रख्यात वैज्ञानिक और पारिस्थिकीविद डॉ. माधव गाडगिल (82) का बीती रात पुणे स्थित डॉ. शिरीष प्रयाग हॉस्पिटल में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से डॉ. माधव गाडगिल का इस अस्पताल में इलाज हो रहा था। यह जानकारी माधव गाडगिल के बेटे सिद्धार्थ गाडगिल ने गुरुवार को दी। पारिस्थिकीविद डॉ. गाडगिल को भारत के अग्रणी पर्यावरण चिंतकों में गिना जाता था। उन्हें 'धरती पुत्र' भी कहा जाता है। उन्होंने पूरी जिंदगी भारत में पर्यावरणीय, खासकर वेस्टर्न घाट की जैव विविधता के बारे में जागरूकता को जिंदा रखने की कोशिश की। माधव गाडगिल ने ही सबसे पहले प्रशासन को चेतावनी दी थी कि पश्चिमी घाट में हो रहे विकास के काम से घाट के जानवरों और पेड़-पौधों और पूरे पारिस्थिकी संतुलन के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। पारिस्थिकीविद डॉ. गाडगिल को 2011 में तैयारी की गई गाडगिल रिपोर्ट एक आईना थी, जिसने उस सोच की कड़वी सच्चाई को दिखाया जो विकास के काम के लिए पर्यावरण जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है।



## दिल्ली में पत्थरबाजी मामला... सपा सांसद से पूछताछ करेगी पुलिस, अब तक 11 गिरफ्तार

मुंबई, 08 जनवरी 2026। दिल्ली में 6 जनवरी की रात फेज-ए-इलाहा मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी को लेकर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के बार-बार कहने के बावजूद नदवी घटनास्थल से नहीं गए और आसपास मौजूद रहे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पत्थरबाजी में शामिल 30 लोगों और सोशल मीडिया पर मस्जिद गिराने की अफवाह फैलाने वाले 10 इन्फ्लुएंसर की पहचान की है। हिंसा के मामले में 6 और गिरफ्तारियों के साथ कुल 11 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। दरअसल पूरा मामला फेज-ए-इलाहा मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने से जुड़ा है। पुलिस की टीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अतिक्रमण हटाने गई थी। इस बीच कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि मस्जिद गिराई जाएगी। जिससे हिंसा भड़की। पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए, 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए।



## जनगणना 2027-पहला फेज 1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा घरों की लिस्टिंग और डेटा जुटाएंगे, ये काम 30 दिन में पूरा होगा

नई दिल्ली, 08 जनवरी 2026। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। इसकी शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 30 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 1 अप्रैल से देशभर में सभी मकानों और परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही परिवारों की अन्य जानकारी भी इकट्ठी की जाएगी, ताकि जनसंख्या गिनने की मजबूत तैयारी हो सके। सरकार ने यह भी कहा कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने



(सेल्फ एन्स्युरेशन) का विकल्प भी दिया जाएगा। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था, जो अब 2027 में पूरी होगी।

## जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी

सरकार ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल एप के जरिए जानकारी जुटाएंगे। मोबाइल एप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से जनगणना बहुत हद तक पेपरलेस होगी। ये एप Android और iOS दोनों पर काम करेंगे। जाति से जुड़ा डेटा भी डिजिटल तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति की गिनती शामिल होगी। इससे पहले अंग्रेजों के समय 1931 तक जाति आधारित जनगणना हुई थी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने अप्रैल में लिया था। 2011 की पिछली जनगणना के अनुसार, भारत की आबादी करीब 121 करोड़ थी, जिसमें लगभग 51.5% पुरुष और 48.5% महिलाएं थीं।

के समय इस पैप से तुरंत पता चल जाएगा कि किस घर में कितने लोग रहते हैं। होटलों में भी श्रमता के हिसाब से कितने लोग रहे होंगे। इस व्योरे से बचाव के लिए जरूरी तमाम नौका, हेलिकॉप्टर, फूड पैकेट आदि की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी।

## स्टार्टअप और एआई एंटरप्रेन्योर भारत के भविष्य के सह-निर्माता : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, 08 जनवरी 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि स्टार्टअप और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निर्माता हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल्स को स्थानीय और स्वदेशी कंटेंट के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बातें आज नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर 12 भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) स्टार्ट-अप के साथ एक राउंडटेबल बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहीं। ये स्टार्ट-अप आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में आयोजित होने वाली 'एआई फॉर ऑल: ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज' के लिए चयनित हुए हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में नवाचार और बड़े पैमाने पर तकनीक के कार्यान्वयन की अपार क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया के सामने 'मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड' की भावना को प्रतिबिंबित करने वाला विशिष्ट एआई मॉडल



प्रस्तुत करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई समाज में व्यापक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है और भारत अगले महीने आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के माध्यम से वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत एआई का प्रभावी उपयोग कर परिवर्तन लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारतीय एआई मॉडल नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल स्थानीय एवं स्वदेशी कंटेंट तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दें। साथ ही, उन्होंने स्टार्ट-अप से वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करने और क्रियाशील, समावेशी एवं फ्रूगल इनोवेशन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एआई स्टार्ट-अप और उद्यमियों को आशवासन दिया कि उनके एआई मॉडलों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। राउंड टेबल में शामिल एआई स्टार्ट-अप से भारत में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की और कहा कि एआई क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण नवाचार और क्रियान्वयन का वैश्विक केंद्र भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है।

## तेलंगाना में कार डिवाइडर से टकराई, 4 छात्रों की मौत

तेलंगाना, 08 जनवरी 2026। तेलंगाना के रंग रेड्डी जिले के चेवेल्ला इलाके में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में ICFAI विजयन स्कूल के चार छात्रों की मौत हो गई। हादसे में एक छात्र घायल है। इसकी हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक कार डिवाइडर से टकराने के बाद पेड़ में घुस गई। पुलिस ने बताया का हादसा रात करीब 1:30 बजे मोकोला धान क्षेत्र में हुआ। सभी छात्र दोस्त की जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। स्पीड ज्यादा तेज होने के कारण ड्राइवर ने कार से कंट्रोल खो दिया। पुलिस ने बताया कि सभी मृतकों और घायल की पहचान कर ली गई है। मृतकों के



नाम कारगयाला सुमित (20), निखिल (20), देवाला सूर्या तेजा (20) और बलमूरी रोहित (18) हैं। घायल छात्र का नाम सुंकारी नक्षत्र है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया जिसका इलाज जारी है।

## बेटे के निधन से दूटे अनिल अग्रवाल, अपनी 75 प्रतिशत संपत्ति दान करने का संकल्प दोहराया

नई दिल्ली, 08 जनवरी 2026। भारत के दिग्गज उद्योगपति और वेदांता रिसेसंस के संस्थापक अनिल अग्रवाल इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन और अधिकारमय दौर का सामना कर रहे हैं। अपने जवान बेटे अग्निवेश अग्रवाल के आकस्मिक निधन ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। इस असीम दुःख की घड़ी में अनिल अग्रवाल ने एक ऐसा फैसला दोहराया है जिसमें पूरी दुनिया को उनकी उदारता का कायल बना दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वह अपनी कुल कमाई का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा परोपकारी कार्यों के लिए दान कर देंगे। पुत्र वियोग का असहनीय दुःख और सादरों का संकल्प : अनिल अग्रवाल ने एक अत्यंत भावुक संदेश साझा करते हुए बताया कि उनके बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 वर्ष की आयु में अमेरिका में इलाज के दौरान कार्डियक



अरेस्ट (दिल का दौरा) से निधन हो गया। एक पिता के लिए अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखना सबसे बड़ा कष्ट है। उन्होंने लिखा कि वह और उनकी पत्नी किरण अग्रवाल अंदर से दूटे चुके हैं। हालांकि, इस दुःख के बीच उन्होंने संकल्प लिया है कि वे अपनी बाकी की जिंदगी और भी अधिक सादगी से जिएंगे और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज के उत्थान में लगाएंगे। अनिल अग्रवाल ने खुलासा किया कि अपनी संपत्ति का 75% हिस्सा दान करने का

वाद उन्होंने अपने बेटे अग्निवेश से ही किया था। उन्होंने कहा कि उनके और उनके बेटे के सपने एक समान थे। अग्निवेश चाहते थे कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न रहे। बेटे के जाने के बाद अनिल अग्रवाल ने इस प्रतिज्ञा को और अधिक मजबूती दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब उनका हर प्रयास और उनकी हर कमाई उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगी जिससे गरीबों और वंचितों का भला हो सके। अनिल अग्रवाल की कहानी शून्य से शिखर तक पहुंचने की एक मिसाल है। 1954 में बिहार के पटना में जन्मे अनिल ने अपने पिता के साथ कबाड़ के छोटे से कारोबार से शुरुआत की थी। मात्र 19 साल की उम्र में वे कुछ कर गुजरने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे। कई बार असफलताओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 1976 में वेदांता ग्रुप की नींव रखी।



# सीएम ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक तय किया मुख्यमंत्री साय ने अंबिकापुर पहुंचकर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव की दिवंगत मां स्वर्णलता सिंहदेव के तेरहवीं में श्रद्धांजलि अर्पित की...

—संवाददाता—  
अम्बिकापुर, 08 जनवरी 2026  
(घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को हेलीकॉप्टर से अंबिकापुर पहुंचकर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव की दिवंगत मां स्वर्णलता सिंहदेव के तेरहवीं कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्णलता सिंहदेव के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शांति संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उनके साथ इस कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता भी मौजूद थे। स्वर्णलता सिंहदेव का निधन 26 दिसंबर 2023 को रायपुर के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ था। उनकी तेरहवीं के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्रह्मभोज कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले, उन्होंने पीजी कॉलेज स्थित हेलीपैड पर मंत्री, विधायक और अन्य नेताओं से



स्वागत लिया और फिर हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव के मनेंद्रगढ़ रोड स्थित पंचायत गार्डन निवास स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद चिंतामणि महाराज, लुंडा विधायक प्रबोध मिंज, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्यो, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, वन विकास निगम के अध्यक्ष

रामसेवक पैकरा, पूर्व सांसद राजनांदगांव अभिषेक सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, नगर पालिक निगम अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल जैसे कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने शोक व्यक्त

करते हुए कहा, 'मैं यहां हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव की मां स्वर्णलता सिंहदेव को विसंग श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आया हूँ।' इस दौरान उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने जीरामजी योजना के संदर्भ में बात करते हुए कहा, 'यह योजना पूरे



देश के लिए कई ट्रिप्टिकोग से फायदेमंद है। अब मजदूरों को 100 दिन की बजाय 125 दिन तक रोजगार मिलेगा, साथ ही एक सप्ताह के भीतर मजदूरी का भुगतान भी सुनिश्चित होगा। अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो पेनाल्टी भी लगेगी। इससे ज्यादा काम और ज्यादा मजदूरी दोनों मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के किसान अब पहले से ज्यादा राहत महसूस करेंगे, क्योंकि धान का कटोरा

होने के कारण पहले किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 'मुख्यमंत्री ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर भी चुर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का यह संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाएगा। इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर

उन्होंने आश्वासन दिया कि तीन महीने बाद, यानी मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उनका मानना है कि यह केवल राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि यहां के नागरिकों के समग्र विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि राज्य में विकास की गति तेज हो रही है और आगामी समय में छत्तीसगढ़ में रोजगार, किसानों की स्थिति में सुधार, और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं और आम नागरिकों में सकारात्मक माहौल पैदा किया, और सीएम की उपस्थिति ने राज्य की वर्तमान विकास योजनाओं और भविष्य के लक्ष्यों के प्रति विश्वास और उत्साह को और मजबूत किया।

## गुरु गोविन्द सिंह किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, अपितु अन्याय के खिलाफ लड़े



—संवाददाता—  
अम्बिकापुर, 08 जनवरी 2026  
(घटती-घटना)।

सर्व समाज एकता मंच ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती उपलक्ष्य पर गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत फादर विलियम ने सर्व समाज के गठन के उद्देश्यों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भारत एक ऐसा बगीचा है जहां विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। यही हमारे देश की खासियत है कि हमारे धर्म, वंशभूमी, खानपान अलग है पर हम सभी मानव प्रेम के सूत्र में बंधे हैं। इसी बात की शिक्षा हमें गुरु गोविंद सिंह से मिलती है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश्चंद्र त्रिपाठी ने गुरु गोविंद सिंह को सर्व समाज का गुरु बताया, उन्होंने कहा कि वह किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं लड़े अपितु अन्याय के खिलाफ लड़े। वरिष्ठ साहित्यकार तपन बनर्जी ने पीर भीखम शाह और पीर बुधु शाह के संस्मरण बताए। कैसे पीर बुधु शाह ने अपने परिवार और अपनी जान गुरु के लिए चोखार कर दी। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद हिंदू और मुसलमानों, दोनों के ही प्रिय थे। चरनप्रित सिंह ने स्लाइडों के माध्यम से गोविंद राय के गुरु गोविंद बनने के सफर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे गुरु नानक देव के मानवता संबंधित विचार गुरु गोविंद

जी की विरासत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। गुरु गोविंद के विचार 'मानस की जात सब एक पहचानबो' आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। कलीम ने गुरु गोविंद के प्रेम और भाईचारे के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई। बालक एकमजोत सिंह ने गुरुवाणी के शब्द को हारमोनियम प्रस्तुत किया। इस दौरान सजितेंद्र सिंह सोझी ने गुरु गोविंद जी की अन्याय के खिलाफ लड़े गए युद्ध का विश्लेषण किया। कैसे गुरु जी ने अपना सर्वस्व उन लोगों के लिए चोखार कर दिया जो शोषित थे, जो पीड़ित थे, अपने बच्चों का बलिदान कोई विरला ही कर सकता है। प्रीतपाल सिंह ने गुरु के अध्ययन के बारे में बताया, वे कई भाषाओं के विद्वान थे, 52 कवि उनके दरबार में थे। 1500 के लगभग पृष्ठों का ग्रंथ श्री 'दशम ग्रंथ' में उनकी लेखनी आज भारतीय इतिहास की विरासत है। इतिहास जी ने सभी उपस्थित जनों को धन्यवाद दिया तथा प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस मौके पर वेद प्रकाश, उर्स लाइन की सिरस्टर्स, फादर, बच्चे, सीपी शुक्ला, अनंत सिन्हा, सोनू भामरा, गुरसेवक, स. महेंद्र सिंह टुटेजा, गुरुद्वारा के पूर्व अध्यक्ष स. रघुवीर सिंह छाबड़ा, फौजी सुरेंद्र सिंह भामरा, थियोडोर लकरा, चरणजीत कौर, नईम परवेज व अन्य नागरिकगण मौजूद थे।

## सरगुजा की कब्बड़ी टीम पहली बार 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य सिनियर चैम्पियनशीप में होगी शामिल



—संवाददाता—  
अम्बिकापुर, 08 जनवरी 2026  
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य की 25वीं छत्तीसगढ़ राज्य सिनियर (महिला/पुरुष) कब्बड़ी चैम्पियनशीप 2025 का आयोजन 9 से 11 जनवरी तक छत्तीसगढ़ कब्बड़ी संघ के तत्वधान में एमिच्योर कब्बड़ी एसोसिएशन कोरबा के लाल मैदान दर्रा में किया जा रहा

है। जिसके लिए पहली बार सरगुजा जिले की टीम गुरुवार को कोरबा के लिए रवाना हुई है। जिला कब्बड़ी संघ सरगुजा की स्थापना के 2 महीने बाद सरगुजा के खिलाड़ी अब राज्य स्तर पर अपने खेल कौशल का परिचय देने के लिए तैयार हो चुके हैं, और सरगुजा के खिलाड़ी राज्य स्तरीय ओपन कब्बड़ी चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए हैं। जिला कब्बड़ी

संघ के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर के निर्देशन पर संघ के सचिव अमितेश पाण्डेय और सह सचिव निशांत गोल्डी सिंह, टेक्निकल हेड राजेश प्रताप सिंह, रजत सिंह ने टीम को राज्य स्तरीय कब्बड़ी चैम्पियनशिप के लिए रवाना किया। बालक-बालिका दोनों ही वर्ग में आयोजित इस चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाली बालिका टीम में उक्त खिलाड़ी कोरबा के लिए रवाना हुए हैं।

**बालिक वर्ग में:** रेमूनि पैकरा, अनिका पैकरा, गीता पैकरा, अलीशा एका, सुशीला पैकरा, दीपिका राजवाड़, पशिका पैकरा, देवती पैकरा, हिमेश्वरी और निक्की पैकरा शामिल हैं।  
**बालक वर्ग में:** सोपाल पैकरा, अमताल, कुनाल पैकरा, नन्दकुमार, लक्ष्मी पैकरा, सिद्धन्तर राम, सुखदेव पैकरा, विमल सिंह, अरविंद और शेर सिंह शामिल हैं। टीम में कोच अनुराग वेक भी खिलाड़ियों के साथ रवाना हुए हैं।

## दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए शहर की छात्रा शिल्पी का चयन

—संवाददाता—  
अम्बिकापुर, 08 जनवरी 2026  
(घटती-घटना)।

शहर की होनहार छात्रा शिल्पी विश्वकर्मा ने दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए चयनित होकर जिले का मान बढ़ाया है। वे सरगुजा जिले से चयनित होने वाली एकमात्र छात्रा हैं। राष्ट्रीय युवा उत्सव में देश के 28 प्रदेशों के चुने हुए प्रतिभागी भाग लेंगे। इन प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के दिल्ली रवाना होने के पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साहय द्वारा मुख्यमंत्री निवास में सेंट्र ऑफ सैरेमनी का आयोजन कर उन्हें दिल्ली रवाना

किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में प्रतिभागियों का लीडरशिप असेसमेंट किया गया। जिसमें पांच विषयों में 6 अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने हेतु चयनित किया गया है। छात्रा शिल्पी विश्वकर्मा पुत्री अमित विश्वकर्मा निवासी गांधीनगर ने बताया कि चयन के प्रारंभिक चरण में उन्होंने वरिष्ठ भारत में मंदिरों की स्थापत्य शैली विषय पर अपना निबंध ऑनलाइन भेजा था। इसके बाद उन्हें रायपुर बुलाया गया था रायपुर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद उन्हें 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला है।

किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में प्रतिभागियों का लीडरशिप असेसमेंट किया गया। जिसमें पांच विषयों में 6 अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेने हेतु चयनित किया गया है। छात्रा शिल्पी विश्वकर्मा पुत्री अमित विश्वकर्मा निवासी गांधीनगर ने बताया कि चयन के प्रारंभिक चरण में उन्होंने वरिष्ठ भारत में मंदिरों की स्थापत्य शैली विषय पर अपना निबंध ऑनलाइन भेजा था। इसके बाद उन्हें रायपुर बुलाया गया था रायपुर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद उन्हें 12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला है।

## फाइनेंस कंपनी के दबाव से परेशान युवक ने दी जान

—संवाददाता—  
अम्बिकापुर, 08 जनवरी 2026  
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के ग्राम धनगांव में फाइनेंस कंपनी के दबाव से परेशान युवक ने कीटनाशक सेवन कर आत्महत्या कर ली। वह अपने पिता के नाम से ट्रेक्टर फाइनेंस कराया था। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिला के ग्राम धनगांव का तनमय सना पिता मंगल सना 29 वर्ष, 6 जनवरी को फाइनेंस से मोबाइल फोन में बात करने के बाद कीटनाशक का सेवन कर लिया था, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता मंगल सना ने पुलिस को बताया है कि दो साल पहले उनके नाम पर ट्रेक्टर फाइनेंस हुआ था, जिसका पहला किस्त एक लाख 50 हजार रुपये उन्होंने पटा दिया था। इसके बाद उनका लड़का तनमय ही ट्रेक्टर चलवा रहा था। 6 जनवरी को शाम करीब 6-7 बजे फाइनेंस कंपनी से फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि दूसरा किस्त 80 हजार रुपये है। इसकी जानकारी वह अपने पुत्र तनमय को देते हुए कहा कि ट्रेक्टर से तुम काम करा रहे हो, इसका किस्त पटा दो। इसके बाद तनमय मोबाइल फोन से फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से कुछ बात किया और 7.30 बजे के लगभग कीटनाशक सेवन कर लिया। परिजन उसे बलरामपुर जिला अस्पताल लेकर गए, यहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने 6 जनवरी को ही दे रात उसे रेफर कर दिया था। यहां इलाज के दौरान 8 जनवरी को सुबह 11 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है।



## खड़े ट्रक से टकराए बाइक सवार युवक की मौत

—संवाददाता—  
अम्बिकापुर, 08 जनवरी 2026  
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग पर स्थित लालमाटी के पास बुधवार को बाइक सवार युवक खड़े ट्रक के पीछे टकरा गया था। दुर्घटना में वह गंभीर रूप से जखमी हो गया था। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार संतोष नोर्सिया पिता चुरन नोर्सिया उम्र 37 वर्ष ग्राम दामा थाना लुण्डा का रहने वाला था। वह बुधवार को अंबिकापुर के गंगापुर स्थित दशरुम कार्यक्रम में आया था। यहां से वापस अपने घर लौट रहा था। अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग पर स्थित लुचकी घाट के पास पूर्व से खड़े ट्रक के पीछे टकरा गया। दुर्घटना में वह गंभीर रूप से जखमी हो गया था। पुलिस ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवया। यहां जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।



## कीटनाशक का सेवन करने से इनकी भी गई जान

—संवाददाता—  
अम्बिकापुर, 08 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

धौपुर थाना अंतर्गत ग्राम डकई निवासी सुधनी पति बृजमोहन 46 वर्ष, तीन जनवरी को अज्ञात कारणों से जहर सेवन कर ली। परिजन उसे अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए थे, यहां बुधवार को दोपहर करीब 12.30 बजे उसकी मौत हो गई। अस्पताल से मिली सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुक्तिका के शव का पोस्टमार्टम कराया है।

## ऋण समय पर चुकाने वाले दिव्यांग हितवाहियों का हुआ सम्मान छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम ने अध्यक्ष दी स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी

—संवाददाता—  
अम्बिकापुर, 08 जनवरी 2026  
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) श्री लोकेश कावडिया के सरगुजा जिला दौर कार्यक्रम के अंतर्गत आज कलेक्टर सभाकक्ष में दिव्यांग हितवाहियों के सम्मान एवं संवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार ऋण योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर उसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण रूप से चुकाने वाले सरगुजा जिले के तीन दिव्यांग हितवाहियों को अध्यक्ष श्री कावडिया द्वारा श्रीफल एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मानित हितवाहियों में मैनपाट की श्रीमती सनमति, पिता भागवत,



लुण्डा के श्री कुंजर साय, पिता श्री राम तथा लखनपुर के श्री मोहन दास, पिता श्री संवरा दास शामिल हैं। अध्यक्ष श्री कावडिया ने अपने संबोधन में दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम की स्वरोजगार योजना को पुनः प्रारंभ किए जाने की जानकारी दी तथा दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप

से सशक्त बनाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास एवं स्वरोजगार के प्रति सकारात्मक संदेश दिया गया। इस अवसर पर श्री हेरंद पटेल, संचालक सदस्य, छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम, अपर कलेक्टर श्री अमृतलाल धुव, जनसम्पर्क अधिकारी तथा समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती प्रभावति दास सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

## मैनपाट महोत्सव 2026 के आयोजन हेतु पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक संपन्न स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर मिले, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमामयी ढंग से आयोजन सम्पन्न हो : मंत्री अग्रवाल



—संवाददाता—  
अम्बिकापुर, 08 जनवरी 2026  
(घटती-घटना)।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में मैनपाट महोत्सव 2026 के आयोजन हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ श्री विनय अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी तीन दिवसीय मैनपाट

महोत्सव 2026 का आयोजन फरवरी माह में सम्भावित तिथि 13, 14 एवं 15 फरवरी को रोपाखार जलाशय के समीप किया जाना है। बैठक में मैनपाट महोत्सव के ध्व्य और गरिमामय आयोजन के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा, तिथि, समय, अतिथियों, कलाकारों, प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभागीय स्टॉल, एडवेंचर एक्टिविटी सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि आयोजन में स्थानीय कलाकारों, स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक अवसर मिले।

उन्होंने स्थानीय दुकानदारों को कार्यक्रम स्थल पर स्टॉल आबंटन हेतु स्थान प्रदान करने निर्देशित किया, जिसमें निजी संस्थान भाग ले सकते हैं, उनसे आवेदन आमंत्रित करें। वहीं उन्होंने कहा कि मनोरंजन एवं खेल गतिविधियों, एस्टॉल आदि के लिए स्थान प्रदान किया जाएगा। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा की लोक निर्माण विभाग, वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग विभागीय कार्यों का निर्वहन करें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमामयी ढंग से आयोजन सम्पन्न हो। शासन-प्रशासन आपसी समन्वय से कार्य करें।

## मंत्री जी के विधानसभा में ही विकास बेबस: गोबरी नदी का पुल 6 महीने बाद भी अधर में



# मंत्री जी के विधानसभा में ही विकास बेबस... गोबरी नदी का पुल 6 महीने बाद भी अधर में

## 15 लाख का रपटा भी मंजूर नहीं, स्थायी पुल कितने साल में बनेगा?

- विकास के दावों के बीच गोबरी नदी बना अभिशाप, जनता परेशान
- निरीक्षण पर निरीक्षण, लेकिन पुल नहीं—मंत्री जी जवाब देंगे?
- 150 करोड़ की घोषणाएं, गोबरी नदी के लिए बजट शून्य?
- मंत्री के गृह क्षेत्र में टूटा पुल, टूटा भरोसा, बरसात फिर न डुबो दे रास्ता—गोबरी नदी पुल पर सन्नाटा
- फोटो खिंचवाने तक सीमित रहे निरीक्षण? पुल कब बनेगा
- सरकार की प्राथमिकता सूची से गायब गोबरी नदी का पुल?
- गोबरी नदी पुल मामला: समाधान की प्रतीक्षा में ग्रामीण

**सूरजपुर, 08 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।** विकास के बड़े-बड़े दावों और करोड़ों की स्वीकृतियों के बीच मंत्री जी के अपने ही विधानसभा क्षेत्र में एक पुल जनता के लिए अभिशाप बन गया है, 30 जून

2025 को गोबरी नदी पर बना पुल धराशायी हो गया था, आज छह महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन न तो स्थायी पुल की दिशा साफ है और न ही वैकल्पिक रपटा पुल की स्वीकृति पूरी हो पाई है, यह मामला केवल एक पुल का नहीं, बल्कि प्राथमिकता, संवेदनशीलता और

जवाबदेही का है, अगर मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही जनता को इस तरह इंतजार करना पड़ रहा है, तो बाकी क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, अब जनता सवाल पूछ रही है, क्या गोबरी नदी का पुल सिर्फ निरीक्षण और भाषणों तक ही सीमित रहेगा, या सच में बनेगा भी?

### वैकल्पिक रपटा पुल भी अधर में...

पुल टूटने के बाद प्रशासन ने तात्कालिक समाधान के तौर पर 15 लाख रुपये के वैकल्पिक रपटा पुल का प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन हेरानी की बात यह है कि इतनी छोटी राशि की स्वीकृति भी अब तक नहीं हो सकी, सवाल सीधा है, जब 15 लाख का रपटा पुल मंजूर नहीं हो पा रहा, तो स्थायी पुल की स्वीकृति कितने साल में मिलेगी?

### मंत्री, निरीक्षण और सिर्फ आश्वासन...

पुल टूटने के बाद कलेक्टर और संबंधित विभाग ने मौके का निरीक्षण किया, क्षेत्र की विधायक एवं महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और उनके पति ठाकुर राजवाड़े ने भी कई बार स्थल निरीक्षण किया, लेकिन सवाल यह है कि निरीक्षण के बाद परिणाम क्या निकला? स्वीकृति कहाँ अटकती है? जनता पूछ रही है कि क्या निरीक्षण सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गए?

### विकास की गाथा, लेकिन गृह क्षेत्र में बटहाली-

जहाँ एक ओर क्षेत्र में विकास की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, वहीं मंत्री के गृह क्षेत्र में लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लंबा चक्कर काटने का मजबूर हैं, स्कूल, अस्पताल, बाजार—सब कुछ दूर हो गया है, आने वाली बरसात को लेकर ग्रामीणों में डर है कि क्या फिर से नदी पार करने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ेगी?

## 150 करोड़ की स्वीकृतियाँ, लेकिन गोबरी नदी के लिए पैसा नहीं?

विगत दिनों क्षेत्र को 150 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृतियाँ मिलने की खबरें आईं, तो फिर सवाल यह भी उठता है, क्या सरकार के पास गोबरी नदी पर पुल बनाने के लिए पैसा नहीं है? या फिर यह पुल प्राथमिकता सूची में ही नहीं है?

### जनता ने खुद संभाला मोर्चा

सरकारी देरी से परेशान होकर ग्रामीणों ने जनसहयोग से रपटा पुल बनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन बिना तकनीकी सहयोग और स्थायी समाधान के यह व्यवस्था भी जर्जर हालत में पहुँच चुकी है, न इसकी मरम्मत हो रही है, न ही कोई सूध लेने वाला नजर आ रहा है।

### सवाल जो मंत्री जी को जवाब देने होंगे...

- पुल टूटे 6 महीने बीत गए—अब तक क्या प्रगति हुई?
- वैकल्पिक रपटा पुल की स्वीकृति किस फाइल में अटकती है?
- स्थायी पुल का टाइमलाइन क्या है?
- क्या मंत्री जी खुद बता पाएंगे कि यह पुल कब बनेगा?

## शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही...निर्माणाधीन मकान का छज्जा भरभराकर गिरा, दबने से 6वीं के छात्र की मौत

**—संवाददाता— बलरामपुर, 08 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।**

जिले के शारदापुर गांव स्थित माध्यमिक शाला खुटहन पारा में शिक्षा विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जहाँ स्कूल के ठीक बगल में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से कक्षा छठवीं में पढ़ने वाले छात्र आलोक कुमार (पिता रमेश देवांगन) की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं परिजनों का रो-रोकर बुगुहा है। जानकारी के अनुसार, घटना मध्यम भोजन अवकाश के दौरान हुई। अवकाश के समय छात्र खेलते हुए स्कूल परिसर के पीछे



निर्माणाधीन भवन के पास पहुँच गया, तभी अचानक मकान का छज्जा भरभराकर गिर पड़ा और आलोक उसके नीचे दब गया। घटना की जानकारी मिलते ही विद्यालय में हड़कंप मच गया।

विद्यालय की शिक्षिका पूजा गुप्ता ने बताया कि मध्यम भोजन का अवकाश किया गया था, इसी दौरान कुछ बच्चे पीछे की ओर गए थे। बच्चों द्वारा सूचना देने पर सभी शिक्षक मौके पर पहुँचे, जहाँ



आलोक खून से लथपथ मलबे में दबा मिला। शिक्षकों और ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विद्यालय में चार शिक्षक

पदस्थ होने के बावजूद छात्र की सुरक्षा को लेकर लापरवाही सामने आई है। घटना ने स्कूल के आसपास चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी और सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

## अवैध धान खपाने लाया जा रहा था धान संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्यवाही, वाहन चालक एवं वाहन मालिकों पर एफआईआर हुआ दर्ज

**—संवाददाता— बलरामपुर, 08 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।**

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाइफनगर श्री नीरनिधि नंदह ने जानकारी दी है कि ट्रक क्रमांक-सीजी 15 ईसी 9169 से अवैध धान का परिवहन किया जा रहा था। जिसे संयुक्त टीम द्वारा ग्राम पेंडरी में पकड़ा गया। ट्रक में 750 बोरी अवैध धान लोड था जिसे जब्त किया गया। धान अवैध धान परिवहन करने के मामले में अज्ञात ट्रक वाहन चालक और वाहन स्वामियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर वाइफनगर के निर्देशानुसार खाद्य, मंडी एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध धान परिवहन पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के



दौरान 05 जनवरी 2026 को रात लगभग 10:30 बजे, ग्राम पेंडरी में तैनात कर्मचारियों के द्वारा रोका गया, परन्तु ट्रक चालक ने मौका पाकर वाहन को वाइफनगर की ओर ले जाया गया। कर्मचारियों के द्वारा ट्रक का पीछा करने पर एक अन्य अज्ञात व्यक्ति जो क्रेटा कार सीजी 15 डीआर 2414 में सवार था उसने कर्मचारियों को धमकाया गया। तत्पश्चात संयुक्त टीम के द्वारा ट्रक की खोज करने पर ग्राम पेंडरी में खड़ा पाया गया।

## धान उठाव में अनियमितता पर प्रशासन की कार्यवाही... संयुक्त टीम के जांच में धान के उठाव में 2600 क्विंटल की पाई गई कमी, जांच उपरान्त जगदंबा राइस मिल लखनपुर को किया गया सील

**—संवाददाता— अम्बिकापुर, 08 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।**

जिले में धान उपार्जन एवं मिलिंग व्यवस्था की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में लखनपुर स्थित जगदंबा राइस मिल में की गई जांच के दौरान धान के भौतिक उठाव में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर लखनपुर तहसीलदार अकिता पटेल, नायब तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक के संयुक्त टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई है।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि राइस मिल द्वारा अभिलेखों में कुल 13,480 क्विंटल धान उठाव दर्शाया गया था, जबकि मौके पर किए गए



भौतिक सत्यापन में केवल 10,880 क्विंटल धान ही उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार कुल 2,600 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जो निरधारित नियमों

एवं शर्तों के विपरीत है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नियमानुसार जगदंबा राइस मिल लखनपुर को सील कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है तथा जांच पूर्ण होने के पश्चात संबंधित राइस मिल प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की धान उपार्जन एवं मिलिंग व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा गड़बड़ी को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण एवं जांच अभियान निरंतर जारी रहेंगे, ताकि कृषकों के हितों की पूर्णतः रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

## नशीले इंजेक्शन तस्करी मामले में बड़ा फैसला...

## सूरजपुर एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

**—संवाददाता— सूरजपुर, 08 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।**

नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के खिलाफ सूरजपुर पुलिस की सख्त कार्यवाही को न्यायालय से भी बड़ी पुष्टि मिली है। बसदेई चौकी पुलिस द्वारा पकड़े गए नशीले इंजेक्शन तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को किसी भी सूत्र में बख्शा नहीं जाएगा। 27 जनवरी 2025 को चौकी बसदेई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम डबरीपारा तालाब के पास मेन रोड पर कार्यवाही करते हुए आरोपी अमजद अली अंसारी, पिता शेख हार्माद अंसारी 30 वर्ष, निवासी ग्राम जूर को उसकी कार क्रमांक CG 16 CG 9664 से गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 34 नग एविल इंजेक्शन एवं 15 नग आईपीपीएल इंजेक्शन बरामद किए गए थे। पुलिस ने नशीली इंजेक्शनों को जब्त कर अपराध क्रमांक 61/25 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। मामले के विवेचक एसआई सकलू राम भगत द्वारा विवेचना के दौरान पुख्ता



साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूर्ण होने के बाद प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध पाते हुए आरोपी अमजद अली अंसारी को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21(सी) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस फैसले से जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस व न्याय व्यवस्था की सख्ती एक बार फिर सामने आई है।

## पुलिस ने नाबालिक से करने वाले आरोपी को पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर

**—संवाददाता— बलरामपुर, 08 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।**

बलरामपुर जिले के कोरोंधा पुलिस ने नाबालिक लड़की को घर छोड़ने के बहाने जबरन दुकानें किया था। शिकायत पर कोरोंधा पुलिस ने अपराध क्रमांक 01/2026 धारा 65 (1) बीएनएस 4 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर। जानकारी के अनुसार दिनांक 06.01.2026 को प्रार्थिया के द्वारा थाना कोरोंधा में उपस्थित होकर इस आशय का एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज



कराई कि इसकी नाबालिक लड़की को आरोपी अजय सोनी पिता मनी सोनी, उम्र 19 वर्ष, ग्राम भगवानपुर, थाना कोरोंधा के द्वारा पीड़िता को ग्राम भगवानपुर से उसके घर छोड़ने के लिये जाते समय ग्राम धुंभरू पाठ में पहुँचकर सड़क के किनारे मुरुम गड्ढा में ले जाकर जबरदस्ती गलत

काम (बलात्कार) किया। पुलिस ने आवेदिका के लिखित आवेदन पत्र के आधार पर थाना कोरोंधा में अपराध क्रमांक 01/2026 धारा 65 (1) बीएनएस 4 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान दिनांक 07.01.2026 आरोपी अजय सोनी पिता मनी सोनी उम्र 19 वर्ष सा. भगवानपुर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

# वर्दी में 'मायावी' खेल, तलवे चाटकर बना रसूख, कोतवाली से सज रहा अवैध कारोबार का जाल



## चिरमिरी में सख्त पुलिसिंग, अवैध कारोबारियों को 'ना'...

यदि चिरमिरी थाना क्षेत्र की बात करें, तो यहां की पुलिसिंग इन दिनों चर्चा में है, चिरमिरी थाना प्रभारी ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त और सख्त रुख अपनाया है, सूत्रों के अनुसार, छोटे से छोटे अवैध कारोबारी तक पर कार्रवाई हो रही है, कई लोग अवैध गतिविधियों से तौबा कर चुके हैं, जबकि नियमों की अनदेखी करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है, चिरमिरी पुलिस इस समय अवैध कारोबार के रास्ते में एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी दिखाई दे रही है।

## 112 के नाम पर वापसी, कोतवाली में 'फील्डिंग'...

बताया जाता है कि उक्त प्रधान आरक्षक 112 सेवा में कार्य करने के नाम पर एमसीबी लौटा था, लेकिन कोतवाली में बैठकर अब फिर से अवैध कारोबार की फील्डिंग करने लगा है, सूत्रों का यह भी आरोप है कि उसने अवैध कारोबारियों को आपस में प्रतिद्वंद्वी बनाकर एक नया, संगठित नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया है, ताकि नियंत्रण भी बना रहे और संरक्षण भी चलता रहे, धीरे-धीरे यह नेटवर्क पैर पसार रहा है, और इसका असर जिला मुख्यालय की कानून-व्यवस्था पर दिखने लगा है।

## जिले की कप्तान की मेहनत पर भारी पड़ते 'पुराने चेहरे' ?

एमसीबी जिले की पुलिस अधीक्षक एक महिला अधिकारी हैं और जिले की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनके प्रयासों की चर्चा भी होती रही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वर्षों से जमे हुए पुलिसकर्मी, खासकर यह मायावी प्रधान आरक्षक, उनकी मंशा को पलौता लगाने का काम कर रहे हैं, यदि संबंधित प्रधान आरक्षक की पूर्व कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी समय रहते संज्ञान में ली जाती, तो संभवतः उसे थाने से दूर रखकर 112 सेवा तक सीमित किया जाता।

## जुआ और अवैध शराब, जिला मुख्यालय में गहराती समस्या...

जिले में खासकर मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में जुआ और अवैध शराब का कारोबार फिर से सिर उठाता नजर आ रहा है, यह न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि आम नागरिकों में पुलिस की निष्पक्षता को लेकर अविश्वास भी पैदा कर रहा है।

## एक जिला, दो कानून ?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब चिरमिरी में सख्त कार्रवाई संभव है, तो मनेंद्रगढ़ में क्यों नहीं? क्या एमसीबी जिले में एक ही कानून के दो मापदंड लागू रहे हैं? क्या अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई थाना प्रभारी की इच्छा पर निर्भर हो गई है, या फिर संरक्षण देने वालों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

## शीर्ष स्तर पर संज्ञान की मांग...

सूत्रों के अनुसार, यह तैनाती पूर्व पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर हुई थी और वर्तमान आईजी के निर्देशों से अमल में लाई गई, ऐसे में अब यह आवश्यक हो गया है कि एमसीबी पुलिस के साथ-साथ सरगुजा रेंज पुलिस का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले का तत्काल संज्ञान ले, यदि समय रहते कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो एमसीबी जिले में एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जा सकती है, जहां अपराधियों का हौसला बढ़ता है और जनता का भरोसा टूटता है, अब निगाहें एमसीबी के पुलिस अधीक्षक और सरगुजा रेंज के आईजी पर टिकी हैं, क्या वे आरोपों की तह तक जाएंगे, या यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा?

## एमसीबी जिले में दोहरी पुलिसिंग... कहीं अवैध कारोबार पर सख्ती... तो कहीं संरक्षण के आरोप...

**एमसीबी में 'मायावी' प्रधान आरक्षक का साया: वर्दी की आड़ में अवैध कारोबार का संगठित खेल ?**

**112 के नाम पर वापसी, कोतवाली में अवैध धंधों की फील्डिंग, जब प्रधान आरक्षक बन जाए 'पावर सेंटर', कानून खुद हो जाए बेबस**

**आईपीएस तक को साधने वाला मायावी प्रधान आरक्षक, एमसीबी में फिर सक्रिय, जशपुर से एमसीबी तक: सवाल के घेरे में एक रहस्यमयी वापसी**

**कोतवाली से अपराध का संचालन ? एमसीबी पुलिसिंग पर गंभीर आरोप, जिस मकसद से भेजे गए थे, क्या उसी पर काम कर रहे हैं ?**

**कानून व्यवस्था से खिलवाड़ या सुनियोजित प्रोपेगेंडा ? अब आईजी-एसपी की बारी: कब टूटेगा 'मायावी' तंत्र ?**

-रवि सिंह-

एमसीबी, 08 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

कानून की सबसे बड़ी ताकत समानता और निष्पक्षता होती है, लेकिन जब एक ही जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अलग-अलग पुलिसिंग दिखाई दे, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि कानून के साथ खुला मजाक है, एमसीबी जिला में यही हो रहा है—कहीं अवैध कारोबार पर सख्त प्रहार, तो कहीं उसी अवैधता को वर्दी की छाया में संरक्षण, चिरमिरी में थाना प्रभारी ने साफ सदेश दिया अवैध कारोबार बंद होना नहीं। नतीजा सबसे सामने है—या तो कारोबार बंद, या सलाखों के पीछे, यह दिखाता है कि इच्छाशक्ति हो तो कानून काम करता है, लेकिन मनेंद्रगढ़ की तस्वीर इसके ठीक उलट क्यों है? यहां जुआ और अवैध शराब का जाल फल-फूल रहा है और आरोप है कि यह सब एक प्रधान आरक्षक के संरक्षण में चल रहा है, यह आरोप मामूली नहीं, पुलिसिंग की आत्मा पर धब्बा है, जिले की कानून-व्यवस्था को

लेकर उठ रहे सवाल अब केवल सामान्य आरोप नहीं रह गए हैं, बल्कि एक 'मायावी' प्रधान आरक्षक की भूमिका को लेकर गंभीर और सुनियोजित आरोप सामने आ रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक, यह कोई साधारण पुलिसकर्मी नहीं, बल्कि ऐसा चेहरा है जिसकी चालाकी और प्रभाव में बड़े-बड़े अधिकारी यहां तक कि आईपीएस स्तर के अफसर और निरीक्षक भी आ जाते हैं, जब-जब ऐसा हुआ है, तब-तब कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है यह कटु सत्य अब किसी से छिपा नहीं।

बता दे की जिले में इन दिनों पुलिसिंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक ही जिले में, एक ही कानून के तहत काम कर रहे पुलिस के बीच अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आ रही है, कहीं अवैध कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, तो कहीं उन्हीं अवैध गतिविधियों के फलने-फूलने के आरोप लग रहे हैं, एमसीबी जिले में सामने आ रही यह दोहरी पुलिसिंग गंभीर जांच और त्वरित सुधार की मांग करती

## 'तलवे चाटने' की कला और वर्दी की गिरती गरिमा

सूत्रों का दावा है कि संबंधित प्रधान आरक्षक अधिकारियों को खूश करने की कला में इस हद तक माहिर है कि वर्दी की गरिमा तक दांव पर लग जाती है, आरोप है कि किस तरह वह अपने वरिष्ठों को साधकर अवैध कारोबार की नींव रखता है, यह बात विशेष के भीतर वर्षों से चर्चित रही है, कहा जा रहा है कि जशपुर से एमसीबी में उसकी वापसी भी उसी 'कला' का नतीजा है, उक्त अधिकारी की कृपा और किस 'गिड़गिड़ाहट' के बाद यह हुआ, यह चर्चा महज गलियारों तक सीमित नहीं रही।

**क्या अब होगी निष्पक्ष जांच? जिले में यह सवाल आम है कि**

**क्या यह प्रधान आरक्षक 112 की भूमिका में है या कोतवाली से अवैध कारोबार का संचालन कर रहा है ?**

**क्या उसकी तैनाती नियमों के अनुरूप है ?**

**और सबसे अहम—क्या आरोपों की स्वतंत्र जांच होगी ?**

है, यदि समय रहते अवैध कारोबारियों और उन्हें संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मीयों पर सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो जिले में कानून-व्यवस्था पर जनता का भरोसा और

**मनेंद्रगढ़ में आरोप—एक प्रधान आरक्षक के संरक्षण में फल-फूल रहा अवैध कारोबार**

इसके ठीक उलट तस्वीर मनेंद्रगढ़ से सामने आ रही है, जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में सूत्रों का दावा है कि जुआ और अवैध शराब जैसे कारोबार खुलेआम फल-फूल रहे हैं, आरोप है कि एक मायावी प्रधान आरक्षक के संरक्षण में यह अवैध नेटवर्क संचालित हो रहा है, बताया जा रहा है कि यही प्रधान आरक्षक पहले कोरिया जिला से अपनी कथित दोषपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण हटाया गया था और बाद में जशपुर जिला भेजा गया।

कमजोर हो सकता है, अब निगाहें जिला पुलिस प्रशासन पर टिकी हैं, क्या वह चिरमिरी मॉडल को पूरे जिले में लागू करेगा, या मनेंद्रगढ़ की यह स्थिति यूं ही बनी रहेगी।

## पुराने रिकॉर्ड और नई तैनाती... सवाल के घेरे में...

यह भी आरोप है कि संबंधित प्रधान आरक्षक की पूर्व कार्यप्रणाली विवादों से भरी रही है, यदि यह सब जानकारी समय रहते संज्ञान में ली जाती, तो उसे थाना-कार्य से दूर रखकर केवल 112 जैसी सीमित भूमिका में ही तैनात किया जाता, लेकिन सवाल यह है कि जिस मकसद से उसे एमसीबी भेजा गया, क्या वह उसी मकसद पर काम कर रहा है या फिर अपना निजी 'प्रोपेगेंडा' गढ़कर पुराने तरीके दोहरा रहा है?

## समाचार पत्र का आग्रह कठोर है...

**दैनिक घटती-घटना समाचार पत्र का आग्रह कठोर है, पर न्यायसंगत है... तुरंत स्वतंत्र जांच... सदिध तैनातियों की रीव्यू और रोडशन... अवैध कारोबार पर जिला-व्यापी एक्शन... और यदि आरोप सही हों तो वर्दी उतारने तक की कार्रवाई... आधे-अधूरे कदम अब काम नहीं आएंगे... कानून का डर अपराधी को होना चाहिए... जनता को नहीं... यदि चिरमिरी मॉडल संभव है, तो मनेंद्रगढ़ अपवाद क्यों ? एक जिला, एक कानून एक पुलिसिंग... यही कसौटी है... इसके बिना भरोसा लौटता नहीं... और बिना भरोसे कानून सिर्फ कागज़ रह जाता है...**

## बेतरतीब खड़े 22 ट्रैलरों पर यातायात पुलिस की सख्त कार्यवाही

-संवाददाता-

कोरिया, 08 जनवरी

2026 (घटती-घटना)।

कोरिया शहर की सड़कों पर बेतरतीब खड़े ट्रैलरों से लग रहे जाम को देखते



हुए यातायात पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े 22 ट्रैलरों पर

**सूचना**

मैं दयाशंकर यादव, आ0 गोपेश यादव, आयु 56 वर्ष, निवासी फुन्दुरिहारी महुआपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0।

मैं दयाशंकर यादव 14403054W रैक हवलदार हूँ, मेरे सेवा पुस्तिका एवं पी0पी0ओ और रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम इन्द्रावती देवी (INRAWATI DEVI) एवं जन्म तिथि 03/03/1972 अंकित हो गया है। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरी पत्नी के आधार कार्ड व पैन कार्ड में नाम इन्द्रावती देवी (INRAWATI DEVI) एवं जन्म तिथि 01/01/1973 अंकित है, जो सत्य एवं सही है।

शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी का सही नाम एवं जन्मतिथि के दर्ज करवाने हेतु यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। यदि भविष्य में मेरी पत्नी के जन्मतिथि एवं नाम के संबंध में किसी प्रकार की कोई वाद विवाद होता है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।

**शपथकर्ता**  
दयाशंकर यादव  
फुन्दुरिहारी महुआपारा, अम्बिकापुर

**नाम परिवर्तन**

मैं अनीता मिंज पति ककील लकड़ा उम 51 वर्ष जाति उरांव निवासी ग्राम रामानुजनागर थाना व तहसील रामानुजनागर जिला सरगुजा (छ0ग0) शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे पुत्र का सही व वास्तविक नाम शौर्य लकड़ा (SHOURY LAKRA) आ, ककील लकड़ा है जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में पुत्र का नाम सैर्य लकड़ा (SAIRY LAKADA) दर्ज है जो कि गलत है।

अतः आज से मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शौर्य लकड़ा (SHOURY LAKRA) आ, ककील लकड़ा के नाम से जाना पहचाना एवं समस्त दस्तावेज में दर्ज किया जाए। इस संबंध में मेरा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

**शपथकर्ता**  
अनीता मिंज  
निवासी ग्राम - रामानुजनागर थाना व तहसील - रामानुजनागर जिला सरगुजा (छ0ग0)

**नाम परिवर्तन**

मैं दिलबन्धु राजवाड़े आ उमाशंकर राजवाड़े उम 21 वर्ष जाति उरांव निवासी ग्राम खरां पोस्ट ओड़गी थाना व तहसील ओड़गी जिला सरगुजा (छ0ग0) शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा सही व वास्तविक नाम दिलबन्धु राजवाड़े (DILBANDHU RAJWADE) आ, उमाशंकर राजवाड़े है जो कि मेरे कक्षा 10वीं की अंकसूची में दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम दीनबन्धु (DEENABANDU RAJVADE) दर्ज है जो कि गलत है।

अतः आज से मुझे मेरे वास्तविक नाम दिलबन्धु राजवाड़े (DILBANDHU RAJWADE) आ, उमाशंकर राजवाड़े के नाम से जाना पहचाना एवं समस्त दस्तावेज में दर्ज किया जाए। इस संबंध में मेरा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

**शपथकर्ता**  
दिलबन्धु राजवाड़े  
निवासी ग्राम - खरां पोस्ट ओड़गी थाना व तहसील ओड़गी जिला सरगुजा (छ0ग0)

**न्यायालय सूरजपुर अधिकारी**  
जिला सरगुजा, छ0ग0

राजस्व सन्-2025-26

**ईश्रतहार**

आगामी तिथि 15/1/2026 इस सार्वजनिक ईश्रतहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता/संस्था/विभाग को एतद द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक कहेवालाल गुप्ता आ0 स्व. मदनलाल गुप्ता, उम लगभग 75 वर्ष, निवासी मेन रोड सूरजपुर थाना व तहसील सूरजपुर द्वारा फौती नामांतरण दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र अंगत धारा 109, 110 छ0ग0 भू-राजस्व संहिता प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि आवेदक के माता के स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लॉट नम्बर 2129/4, 2915/4 रकबा क्रमशः 0.010, 0.010 हे0 है। आवेदक की माता स्व. शशीला देवी की मृत्यु दिनांक 17/08/2008 को होने से उनका नाम विलोपित कर आवेदन पत्र में दर्शित वंशवृक्ष अनुसार फौती नामांतरण नजूल भूमि से संबंधित अभिलेखों में दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया है जो इस न्यायालय में विचारणीय लंबित है। अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई दावा/आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक/लौंगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/आपत्ति दिनांक 15/1/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 26/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

**सील** नजूल अधिकारी सूरजपुर

**न्यायालय नजूल अधिकारी**  
अम्बिकापुर, जिला सरगुजा

राजस्व सन्-2025-26

**ईश्रतहार**

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक बलराज पिता इन्द्रसेन अग्रवाल उम लगभग 62 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी ब्रम्हरोड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा शीट नम्बर-08 मोहल्ला ब्रम्हरोड नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लॉट नम्बर 3230 / 6 रकबा 0.06, 1/2 एकड़ भूमि को बैंक में बंधक रखने की अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-23/01/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक-05/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

**सील** नजूल अधिकारी अम्बिकापुर

**न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के**  
न्यायालय में मामला क्रमांक- 2026010207000017

विषय:-अ-6 मामले की श्रेणी:- राजस्व सन्-2025-26

अम्बिकापुर प.ह.न. 00015 [2534/13 (0.010हे0)] पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार - सुहेल अख्तर, अनावेदक पक्षकार - नजरूननिशा,

**ईश्रतहार**

आवेदक सुहेल अख्तर (आमो) अजीज व अन्य निवासी मोमिनपुरा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 2534/13 रकबा 0.010 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखों से मृतखातेदार नजरूननिशा का नाम विलोपित कर फौती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 30.01.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्रतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2026 को जारी किया जा रहा है।

**सील** उमेश्वर सिंह बाज तहसीलदार, अम्बिकापुर

**न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के**  
न्यायालय में मामला क्रमांक- 2026010207000030

विषय:-अ-6 मामले की श्रेणी:- राजस्व सन्-2025-26

सुभाषनगर प.ह.न. 00017 [158/18 (0.014हे0)] पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार - अंजना वर्मा, अनावेदक पक्षकार - संतोष कुमार वर्मा,

**ईश्रतहार**

आवेदक अंजना वर्मा पति संतोष वर्मा व अन्य निवासी माईस कॉलोनी बिजुरी कॉलेरी जिला शहडोल म0प्र0 के द्वारा ग्राम सुभाषनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 158/18 रकबा 0.014 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखों से मृतखातेदार संतोष कुमार वर्मा का नाम विलोपित कर फौती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 30.01.2026 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्रतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 06/01/2026 को जारी किया जाता है।

**सील** उमेश्वर सिंह बाज तहसीलदार, अम्बिकापुर

**न्यायालय नजूल अधिकारी**  
अम्बिकापुर, जिला सरगुजा

राजस्व सन्-2025-26

**ईश्रतहार**

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण मुकेश अग्रवाल आ. स्व. साधुराम अग्रवाल, उम-43 वर्ष, विमला देवी पति स्व. साधुराम अग्रवाल, उम 65 वर्ष दोनों निवासी बरेलवा अग्रसेन वाड अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाराय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण के पिता/पति साधुराम अग्रवाल के स्वामित्व व अधिपत्य की मोहल्ला अग्रसेन वाड नगर अम्बिकापुर स्थित भूखण्ड क्रमांक 2741/30 रकबा 0.02 एकड़ भूमि है। भूधायक साधुराम अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 22.03.2017 को हो गई है। अतः भूधायक साधुराम अग्रवाल की मृत्यु हो जाने उपरंत आवेदकगण द्वारा स्वयं को मूलक भूधायक के वैध वारिसान बताते हुए उक्त भूखण्ड से उनका नाम विलोपित कर स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र अंगत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 23/01/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02/01/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

**सील** नजूल अधिकारी अम्बिकापुर

# एक साल में बदली कोरिया भाजपा की तस्वीर

## देवेन्द्र तिवारी बने कार्यकर्ताओं की उम्मीद



- » संगठन, समन्वय और सफलता... भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी का एक साल
- » भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी का कार्यकाल में उपेक्षित कार्यकर्ता बने संगठन की ताकत
- » बूथ स्तर तक पहुंचा भाजपा संगठन, पहले ही वर्ष में देवेन्द्र तिवारी की बड़ी उपलब्धि
- » पहले साल में ही चुनावी जीत और संगठनात्मक मजबूती, देवेन्द्र तिवारी का प्रभावशाली कार्यकाल
- » कार्यालय से बूथ तक भाजपा, देवेन्द्र तिवारी के नेतृत्व में संगठन को मिली नई ऊर्जा
- » एक वर्ष, कई उपलब्धियां, देवेन्द्र तिवारी ने कोरिया भाजपा को दी नई दशा-दिशा
- » भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी का रिपोर्ट कार्ड, संगठन मजबूत, कार्यकर्ता सक्रिय
- » 2026 की अग्नि परीक्षा से पहले देवेन्द्र तिवारी ने संगठन को किया तैयार

# जिलाध्यक्ष 1 वर्ष देवेन्द्र तिवारी का



प्रशासन के साथ संतुलित तालमेल

देवेन्द्र तिवारी के कार्यकाल में जिला प्रशासन के साथ टकराव नहीं, तालमेल की नीति देखने को मिली, जहां जनहित का विषय रहा, वहां संवाद के माध्यम से काम कराया गया, और जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, वहां संगठनात्मक मर्यादा बनाए रखी गई। इस संतुलन की प्रशंसा संगठन और आमजन दोनों करते हैं।

### संगठन को कार्यालय से निकालकर बूथ तक पहुंचाया

बीते वर्षों में कोरिया जिले में भाजपा संगठन को लेकर यह आम धारणा बन चुकी थी कि गतिविधियां केवल भाजपा कार्यालय और कुछ बड़े चेहरों तक सीमित रहती हैं। देवेन्द्र तिवारी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद इस तस्वीर में स्पष्ट बदलाव देखने को मिला, पार्टी के कार्यक्रम अब बूथ स्तर तक नियमित रूप से आयोजित होने लगे। कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ी और संगठनात्मक कार्यक्रम कागजों से निकलकर जमीन पर उतरते नजर आए। बूथ समितियों की सक्रियता और नीचे तक संवाद ने संगठन में नई ऊर्जा धरी।

### हर वर्ग को प्रतिनिधित्व, कार्यकर्ता बनी संतुलन की मिसाल

जिला कार्यकर्ताओं के गठन में देवेन्द्र तिवारी ने हर वर्ग, हर समाज और हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया, ऐसे कई कार्यकर्ता, जो वर्षों से संगठनात्मक पदों से दूर थे, उन्हें जिम्मेदारी मिली, परिणामस्वरूप, पद मिलने के बाद वे कार्यकर्ता पार्टी कार्यक्रमों में नियमित रूप से सक्रिय दिखने लगे, इस कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें अनुभव और नएपन का संतुलन नजर आया नए चेहरे, लेकिन ईमानदारी और समर्पण के साथ संगठन का काम करते हुए।

### चुनावी मैदान में पहली ही परीक्षा में सफलता...

जिलाध्यक्ष बनते ही देवेन्द्र तिवारी को पंचायत और निकाय चुनाव जैसी कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, पटना नगर पंचायत में विरोध के बावजूद गायत्री सिंह को प्रत्याशी बनाकर उन्होंने सबको चौंकाया, तमाम आशंकाओं के बीच भाजपा ने वहां ऐतिहासिक जीत दर्ज की और गायत्री सिंह प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुईं साथ ही गौरव अग्रवाल को पटना नगर पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया, इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सीमित संख्या बल के बावजूद रणनीतिक कौशल दिखाते हुए मोहित पैकरा को अध्यक्ष बनवाने में सफलता मिली, उपाध्यक्ष पद पर भी पार्टी समर्थित प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराई गई, यह सभी उपलब्धियां देवेन्द्र तिवारी की चुनावी प्रबंधन क्षमता को दर्शाती हैं।

### उपेक्षित कार्यकर्ताओं को मिला सम्मान...

कोरिया भाजपा में लंबे समय से यह शिकायत थी कि आम कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय याद किए जाते हैं। देवेन्द्र तिवारी के नेतृत्व में इस सोच को बदलने का प्रयास हुआ, उपेक्षित महसूस करने वाले कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी गईं, बैठकों में उनकी भागीदारी बढ़ी और निर्णय प्रक्रिया में उन्हें जोड़ दिया गया। आज ऐसे कई कार्यकर्ता सक्रिय रूप से संगठन का चेहरा बनते नजर आ रहे हैं।

### मोर्चा-प्रकोष्ठों में नए चेहरों से बढ़ा उस्ताह...

पहली बार मोर्चा और प्रकोष्ठों में वर्षों से चले आ रहे आरक्षित चेहरों की परंपरा टूटी, भाजयुमो, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अजजा और अजा मोर्चा इन सभी में नए और अपेक्षाकृत अतरेखे चेहरों को नेतृत्व दिया गया, इस फैसले से कार्यकर्ताओं में यह संदेश गया कि संगठन में मेहनत करने वालों के लिए आगे बढ़ने के अवसर खुले हैं।

### प्रदेश संगठन के भरोसेमंद सिपाही...

कम समय के राजनीतिक जीवन में देवेन्द्र तिवारी को जिलाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलना यह दर्शाता है कि वे प्रदेश संगठन की नजर में भरोसेमंद माने जाते हैं, विधानसभा, लोकसभा और अन्य राज्यों के चुनावों में उन्हें दी गई जिम्मेदारियों का उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। कोरिया जिला कार्यकर्ता का समय पर गठन भी इसी भरोसे का परिणाम माना जाता है।

### नया भाजपा कार्यालय, स्थायी विरासत...

जिलाध्यक्ष बनते ही पुराने भाजपा कार्यालय के स्थान पर नए भवन के निर्माण की पहल की गई, प्रदेश संगठन की देखरेख में यह निर्माण कार्य जारी है और संभावना है कि एक वर्ष के भीतर कोरिया जिला भाजपा को नया, आधुनिक कार्यालय मिल जाएगा जो संगठन के लिए एक स्थायी आधार बनेगा।



-राजन पाण्डेय-

### कोरिया, 08 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

आइए बताता हूँ संगठन की कसौटी पर नेतृत्व की कहानी राजनीतिक दलों की असली मजबूती चुनावी नारों से नहीं, बल्कि जमीनी संगठन, कार्यकर्ताओं के मनोबल और समावेशी नेतृत्व से तय होती है, कोरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी का एक वर्ष पूरा होना इसी कसौटी पर परखने का अवसर देता है, बीते वर्षों में यह शिकायत आम रही कि संगठन कुछ चेहरों और कार्यालयों तक सीमित रह गया था, आम कार्यकर्ता हाशिए पर था, उसे केवल चुनावी समय याद किया जाता था, पिछले एक वर्ष में जिस बदलाव की चर्चा है, उसका मूल यही है कि संगठन को व्यक्ति-केन्द्रित ढांचे से निकालकर



कार्यकर्ता-केन्द्रित बनाया जाए, बूथ स्तर तक कार्यक्रमों की नियमितता, कार्यकर्ताओं में विविध वर्गों की भागीदारी और उपेक्षित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे संकेत बताते हैं कि दिशा बदलने की कोशिश ईमानदार रही है, चुनावी मोर्चे पर भी नेतृत्व की परीक्षा हुई, विरोध और संशयों के बीच लिए गए निर्णयों ने यह स्पष्ट किया कि रणनीति, संवाद और धैर्य के साथ चुनावी चुनौतियों को साधा जा सकता है, जीत का श्रेय केवल प्रत्याशी को नहीं, बल्कि उस संगठनात्मक मशीनरी को भी जाता है, जो बूथ से लेकर जिला स्तर तक सक्रिय रही, हालांकि, संपादकीय का दायित्व केवल सराहना तक सीमित नहीं, आगे की राह कठिन है, 2026 के निकाय चुनाव ऐसे समय आएंगे जब जन-असंतोष, स्थानीय मुद्दे और प्रशासनिक अपेक्षाएं एक साथ परीक्षा लेंगी, संगठनात्मक मजबूती को जनविश्वास



में बदलना होगा, बिजली, पानी, रोजगार, किसानों और शहरी सेवाओं जैसे मुद्दों पर स्पष्ट और संवेदनशील रुख जरूरी होगा, प्रशासन से संतुलित तालमेल रखते हुए जनहित के परिणाम सामने लाने होंगे, केवल समन्वय की चर्चा पर्याप्त नहीं, नया कार्यालय, नए चेहरे और नई ऊर्जा ये सब साधन हैं, साध्य नहीं, साध्य है, कार्यकर्ता का सम्मान, जनता की सुनवाई और जवाबदेही, यदि यह संतुलन बना रहा, तो संगठन आगे भी मजबूत होगा, यदि नहीं, तो उपलब्धियां कागजों पर जाएंगी, पहला वर्ष दिशा दिखाता है, मंजिल नहीं, नेतृत्व की असली पहचान अगले कदमों से होगी-क्या संगठन जनता की आवाज़ बन पाएगा, क्या कार्यकर्ता स्वयं को सहभागी महसूस करेंगे, और क्या चुनावी सफलता जनहित की नीतियों में बदलेगी। आने वाला समय इन सवालों का उत्तर देगा।



बता दे की भारतीय जनता पार्टी के कोरिया जिला संगठन में देवेन्द्र तिवारी के जिलाध्यक्ष बने एक वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह एक वर्ष संगठनात्मक दृष्टि से न केवल सक्रियता से भरा रहा, बल्कि भाजपा के जमीनी ढांचे को फिर से खड़ा करने वाला भी साबित हुआ। वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रहे कार्यकर्ताओं को मुख्यधारा से जोड़ने, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और चुनावी चुनौतियों में सफलता दिलाने के कारण यह कार्यकाल चर्चा में रहा, एक वर्ष के कार्यकाल में संगठनात्मक विस्तार, कार्यकर्ताओं का मनोबल, चुनावी सफलता और प्रशासनिक संतुलन इन सभी पहलुओं ने देवेन्द्र तिवारी को एक सक्रिय और परिणाम देने वाले जिलाध्यक्ष के रूप में स्थापित किया है, अब देखना यह होगा कि 2026 के चुनावी रण में यह संगठनात्मक ताकत भाजपा को कितनी बड़ी सफलता दिला पाती है।

## आगे की चुनौती 2026 के निकाय चुनाव

आने वाले समय में नगरपालिका परिषद बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा के चुनाव होने हैं, राज्य स्तर पर मौजूद राजनीतिक परिस्थितियों और कुछ जनाक्रोश वाले मुद्दों के बीच यह चुनाव देवेन्द्र तिवारी के लिए अगली कठिन परीक्षा होंगे। संगठनात्मक मजबूती को फिर से चुनावी जीत में बदलना उनकी नेतृत्व क्षमता की असली कसौटी रहेगा।





# मनरेगा पर संकट! कांग्रेस का बड़ा ऐलान... 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलाएगी 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान

## सचिन पायलट बोले... मनरेगा को खत्म करना चाहती है सरकार

रायपुर, 08 जनवरी 2026। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की संयुक्त बैठक राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने ली, जिसमें कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर राज्यों पर बोझ डालने का आरोप लगाते हुए बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। बैठक में 10 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रदेशभर में VB-GRAM-G विधेयक के खिलाफ 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान चलाने का निर्णय लिया। इस दौरान कांग्रेसी रोजगार अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे। ग्राम पंचायत से विधानसभा तक आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा मनरेगा था, जिसे केंद्र सरकार दुर्भावनापूर्ण नाम बदलकर पूरी तरह समाप्त करने में लगी हुई है। एआईसीसी के निर्देशानुसार 10 जनवरी को मनरेगा के मुद्दे पर सभी जिलों में प्रेसवार्ता आयोजित की जाएगी। इसके बाद एक दिवसीय उपवास रखा जाएगा।



### 10 जनवरी को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस

10 जनवरी से 26 फरवरी 2026 तक कांग्रेस 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान चलाएगी। इस दौरान 10 जनवरी को सभी जिला स्तर पर अभियान के औपचारिक शुभारंभ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। प्रस्तावित कानून के ग्रामीण रोजगार और आजीविकाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति मीडिया को संवेदनशील बनाया जाएगा।

इतना ही नहीं 26 जनवरी को हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से इस मुद्दे को पास कराएंगे। चुकी ये मुद्दा जनता का है इसीलिए हमारे एक-एक कदम पर जनता साथ होगी। विधानसभा घेराव

भी किया जाएगा। गांधीवादी तरीके से पूरा आंदोलन किया जाएगा। पायलट ने कहा, इस मामले में भी सरकार सबसे गरीब, वंचित लोगों का हानन करना चाहती है। इसका पूरजो विरोध

किया जाएगा। हमने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एक-एक गांव से लेकर मंडल तक जाएगा, और जनता को जागरूक करेगा। बैठक में सचिन पायलट के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व छिटी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

11 जनवरी को एक दिवसीय उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध : जिला मुख्यालयों या प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, जैसे महात्मा गांधी

### 30 जनवरी को वाई स्टार पर शांतिपूर्ण धरना, फिर 31 से जिलास्तरीय प्रदर्शन

30 जनवरी को वाई और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरने आयोजित किए जाएंगे, जिनमें अहिंसा, संवैधानिक मूल्यों और काम के अधिकार पर जोर दिया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना दिया जाएगा। जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों पर धरने आयोजित किए जाएंगे, जिसके पश्चात VB-GRAM-G विधेयक को वापस लेने और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

### 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा घेराव

पीसीसी के नेतृत्व में राज्य स्तर पर विधानसभाओं का घेराव किया जाएगा, जिसमें अधिकतम मौबिलाइजेशन के माध्यम से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की नीति और राज्यों पर डाले जा रहे बोझ को उजागर किया जाएगा। अभियान के समापन के रूप में एआईसीसी द्वारा चार प्रमुख क्षेत्रीय रैलियों का आयोजन किया जाएगा। स्थलों और तिथियों का विवरण अलग से सूचित किया जाएगा।

या डॉ. बीआर आंबेडकर की प्रतिमाओं के पास पार्टी नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और मनरेगा श्रमिकों की भागीदारी के साथ एक दिवसीय उपवास किया जाएगा।

12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क : सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत स्तर

की चोपलें और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस चरण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के पत्र ग्राम प्रधानों, पूर्व ग्राम प्रधानों, रोजगार सेवकों और मनरेगा श्रमिकों तक पहुंचाए जाएंगे। साथ ही विधानसभा स्तर पर नुकड़ सभाएं और पंच वितरण भी किया जाएगा।

## जनदर्शन में दिव्यांग आर्चरी खिलाड़ियों से मिले सीएम साय सरकार दे रही खेलों को बढ़ावा, छत्तीसगढ़ का नाम करें रोशन : मुख्यमंत्री साय

रायपुर, 08 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग तीरंदाज हरीशचंद्र यादव और लवकी सोनी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम से उच्च स्तरीय खेल उपकरण और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव की बात कही, जिसपर मुख्यमंत्री ने दिव्यांग आर्चरी खिलाड़ियों को तीरंदाजी से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। मुलाकात के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे दिव्यांग तीरंदाजी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और आगामी फरवरी माह में पटियाला में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वे भविष्य में अंतरराष्ट्रीय



आर्चरी स्पर्धाओं में देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें उच्च स्तरीय खेल उपकरण और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खिलाड़ियों की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें हस्तक्षेप सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे

बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दिव्यांग खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं हैं और सही मार्गदर्शन व सुविधाएं मिलने पर वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों तीरंदाजों को अपने खेल कौशल को निरंतर निखारने और पूरी मेहनत व लगन के साथ अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया।

## बिलासपुर यूनिवर्सिटी में बवाल... कुलपति ने साहित्यकार को सभा से निकाला

### बिलासपुर, 08 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित एक राष्ट्रीय परिषदवाद उस समय विवादों के घेरे में आ गया, जब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल और एक आमंत्रित साहित्यकार के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। यह घटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग और साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'समकालीन हिंदी कहानी: बदलते जीवन संदर्भ' विषय पर चर्चा के दौरान हुई। अकादमिक विमर्श के लिए सजे इस मंच पर संवाद की जगह विवाद उस समय हावी हो गया जब कुलपति ने अपने व्यवहार से सबको हैरान कर दिया।

विषय से भटके कुलपति: अपनी कहानी सुनाने पर हुआ ऐतराज : परिषदवाद के दौरान कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया, तो वे निर्धारित विषय 'हिंदी कहानी' पर चर्चा करने के बजाय अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों और



### मुद्दे की बात करें... : साहित्यकार के सुझाव पर भड़के कुलपति

कुलपति के सवाल पर महाराष्ट्र से आए प्रख्यात साहित्यकार मनोज रुपण ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया कि 'यदि चर्चा कार्यक्रम के मुख्य विषय पर केंद्रित रहे, तो बेहतर होगा।' साहित्यकार का इनका कहना ही था कि कुलपति अपना आपा खो बैठे। उन्होंने इसे अपना अपमान माना और सख्त लहजे में कहा, 'बहुत बड़े कहानीकार और विद्वान बन रहे हैं, लेकिन इन्हें तमीज नहीं है कि कुलपति से कैसी बात की जाती है।' उन्होंने संयोजकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन्हें (मनोज रुपण) भविष्य में कभी किसी कार्यक्रम में न बुलाया जाए।

उपलब्धियों का बखान करने लगे। काफी देर पर विवेश तथा निजी जीवन के किस्से सुनाते तक वे अपने गुजराती और बनारसी भाषाई रहे। कार्यक्रम में मौजूद विद्वान और

साहित्यकार इस बात से असहज महसूस करने लगे कि चर्चा मुख्य मुद्दे से भटक रही है। इसी बीच कुलपति ने खुद ही एक साहित्यकार की ओर इशारा करते हुए पूछ लिया, 'भाई साहब, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं?'

### राम से बाहर निकलने का फरमान: अन्य प्रतिनिधियों ने किया बहिष्कार

विवाद यहीं नहीं थमा, कुलपति ने मनोज रुपण को भरी सभा से बाहर जाने का आदेश दे दिया। कुलपति के इस अडिग और अपमानजनक रविये को देख सभागार में मौजूद अन्य प्रोफेसर और दूसरे राज्यों से आए साहित्यकार विरोध करने लगे। जब कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, तो कुलपति ने दौड़क कह दिया कि जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, वे भी बाहर जा सकते हैं। इस अपमान से क्षुब्ध होकर कई वरिष्ठ प्रतिनिधियों और साहित्यकारों ने कार्यक्रम का बीच में ही बहिष्कार कर दिया और सभागार छोड़कर चले गए।

## अब विद्यार्थियों की डिजिटल पहचान... छत्तीसगढ़ में 88.63 प्रतिशत APAAR आईडी बनीं



रायपुर, 08 जनवरी 2026। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत भारत सरकार द्वारा लागू की गई ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री व्यवस्था में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। राज्य में विद्यार्थियों की स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान बनाने की दिशा में तेजी से काम किया गया है, जिसका असर आंकड़ों में साफ नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 57,045 स्कूलों में पढ़ने वाले कुल 57,10,207 विद्यार्थियों में से 50,60,941 छात्रों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी सफलतापूर्वक तैयार की जा चुकी है। यह कुल का 88.63 प्रतिशत है, जो प्रतिशत के आधार पर देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक माना जा रहा है। इसे राज्य के लिए डिजिटल शिक्षा ढांचे की दिशा में बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। जिलावार स्थिति पर नजर डालें तो बेमेतरा (96.40%) और राजनांदगांव (96.38%) जिलों में सबसे अधिक विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी बनाई गई है। इसके अलावा रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोबा, धमतरी, दुर्ग और बलौदाबाजार जैसे जिलों में भी 93 प्रतिशत से अधिक छात्रों की आईडी तैयार हो चुकी है। राज्य के केवल पांच जिले-तारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर और दंतवाड़ा ऐसे हैं, जहां अब तक 80 प्रतिशत से कम विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी बन पाई है। हालांकि इन जिलों में भी शेष छात्रों की आईडी बनाने का कार्य लगातार जारी है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य रूप से तैयार कर ली जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में स्कूल स्तर पर शिक्षकों और शिक्षा विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान मिलती है। इसमें छात्र की शैक्षणिक उपलब्धियां, प्रमाण-पत्र, मार्कशीट और क्रेडिट्स सुरक्षित डिजिटल रूप में दर्ज रहते हैं।

## बिलासपुर-राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जज की ऑफिशियल आईडी पर आया ई-मेल कैंपस खाली कराया, बम-स्वचायड कर रही जांच

बिलासपुर, 08 जनवरी 2026। राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बिलासपुर जिला कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस हाई अलर्ट पर है, जिला न्यायालय परिसर सील कर दिया गया है। डॉग स्कॉड और बम निरोधक दस्ता जांच कर रही है। धमकी देने वाले की तलाश जारी है। इससे पहले राजनांदगांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता को आधिकारिक ई-मेल आईडी पर अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भेजी थी। धमकी भरा मेल मिलते ही पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे जिला न्यायालय परिसर को तुरंत खाली कराया गया। सभी जजों, वकीलों,



न्यायालय कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आने-जाने वाले रास्तों पर भी सख्त निगरानी रखी जा रही है। जिससे जीई रोड पर काफी भीड़ जमा हो गई है। वहीं ऐहतिगत, रायपुर और धमतरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बम स्वचायड और डॉग स्कॉड की टीम पहुंची है। हर मॉडल में जांच हो रही है। परिसर में घूम रहे अनजान लोगों से पूछताछ की जा रही है। अलर्ट जारी किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बम

निरोधक दस्ता और अन्य जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। पूरे परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है। शुरुआती जांच में अब तक किसी भी सदिग्ध वस्तु या विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ऐहतिगतन सुरुआत व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक, न्यायालय परिसर को आरडीएक्स से उड़ाने की बात कही गई है। जिसके लिए गुस्वार सुबह 10 बजकर 7 मिनट पर मेल आया। दोपहर 2:35 बजे तक का समय दिया गया था। यह मेल एक इंटरनेशनल नंबर का इस्तेमाल कर भेजा गया है। जिससे भेजने वाले की पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। मेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

## स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि : सीएम साय

रायपुर, 08 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित इंटोमेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर टवीट करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि यह उपलब्धि राज्य की आधुनिक, तकनीक-सक्षम और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य अवसरचना का सशक्त प्रमाण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वास्थ्य

सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। IPHL रायपुर को मिला NQAS सर्टिफिकेशन इस दिशा में किए गए सतत प्रयासों का परिणाम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य जांच, योग निदान और प्रयोगशाला सेवाएं राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संचालित की जा रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस प्रमाण से आम नागरिकों को सटीक, समयबद्ध और भरोसेमंद जांच सुविधाएं और अधिक सुलभ होंगी।

## छत्तीसगढ़ शराब घोटाला... सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

बिलासपुर, 08 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक याचिकाकर्ता सौम्या चौरसिया को अंतरिम राहत प्रदान की है। इस मामले में कोर्ट अपना निर्णय 13 जनवरी को सुनाएगा।

दरअसल, एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ सौम्या चौरसिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालयने उन्हें शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद अब सभी की निगाहें 13 जनवरी को आने वाले फैसले पर टिकी हैं, जो इस मामले में आगे की दिशा तय करेगा।



सौम्या चौरसिया

दरअसल, एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ सौम्या चौरसिया ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालयने उन्हें शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद अब सभी की निगाहें 13 जनवरी को आने वाले फैसले पर टिकी हैं, जो इस मामले में आगे की दिशा तय करेगा।